क्रमांक 15011/35/2021-जेयूएस(एयू)

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग (समन्वय)

जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 16 सितंबर, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: मंत्रिमंडल के लिए अगस्त, 2021 माह के मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को न्याय विभाग के अगस्त, 2021 माह के मासिक सार की एक प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एम एस पी दारा)

अवर सचिव (समन्वय)

संलग्न: यथोपरि ।

प्रति

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः:

निदेशक [डॉ. टीना सोनी], कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषितः:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार के सभी सचिव।
5. विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में अगस्त, 2021 माह का मासिक सार

अगस्त, 2021 माह के लिए न्याय विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

1. न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:

न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी के बाद, संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 19.08.2021 को जारी किए गए हैं। न्याय विभाग के लगातार प्रयासों के कारण, सीएसएस के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने न्याय विकास पोर्टल पर न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर ऑनलाइन डेटा अपलोड करने में तेजी ला दी है। 3437 पूर्ण कोर्ट हॉलों में से 3198 को जियो-टैग किया गया है और 3590 पूर्ण आवासीय इकाइयों में से 2952 आवासीय इकाइयों को जियो-टैग किया गया है।

2. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना:

- उड़ीसा उच्च न्यायालय अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग नियमावली, 2021 को 28 जुलाई को अधिसूचित करने पर, 2 अगस्त, 2021 को उड़ीसा उच्च न्यायालय में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय में, अदालती कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण सार्वजनिक महत्व के चुनिंदा मामलों में कार्यवाही का सीधा प्रसारण के साथ पायलट आधार पर शुरू किया गया है।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में मामलों के त्वरित निपटान के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर से सुसज्जित 5 (पांच) मोबाइल ई-कोर्ट स्थापित किए हैं, जिससे पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली जिलों में न्याय तक पहुंच आसान हो सके।
- उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कागज रहित वातावरण में अधीनस्थ न्यायालयों को उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्णयों के सुरक्षित और तात्कालिक संप्रेषण की सुविधा प्रदान करने के लिए ऑर्डर कम्युनिकेशन पोर्टल (ओसीपी) नामक एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिससे पत्राचार के पारंपरिक तरीकों में लगने वाले संसाधनों और समय की बचत होगी।

3. व्यवसाय करने में आसानी (ईओडीबी):

- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें दायर किए गए वाणिज्यिक मामलों, लंबित और लिए गए औसत समय के साथ निपटाए गए मामलों, केस प्रबंधन सुनवाई, पीआईएमएस, ई-फाइलिंग और ई-समन, विवरण आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- इस महीने के दौरान 4 और राज्यों को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस के साथ एनजेडीजी और ई-कोर्ट को जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से मंजूरी मिल गई है, जिससे ऐसे कुल राज्यों की संख्या 17 हो गई है।

4. टेली-लॉ:

64,894 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसमें 18,553 महिलाएं, 19,185 अनुसूचित जाति, 12,804 अनुसूचित जनजाति और 21,351 ओबीसी लाभार्थी शामिल थे। 31 अगस्त, 2021 तक कुल दी गई सलाह 11,06,267 थीं। 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 107 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें 5579 राज्य स्तरीय समन्वयक/जिला प्रबंधक/ग्राम स्तरीय उद्यमी/पैरा लीगल स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

5. न्याय बंधु:

माह के दौरान 118 नए वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3181 वकीलों ने पंजीकरण कराया है। असम राज्य में न्याय बंधु के तहत पहला ट्रांसजेंडर प्रो-बोनो वकील पंजीकृत हुआ। न्याय बंधु पैनल के तहत अब तक 12 उच्च न्यायालयों द्वारा 416 प्रो बोनो वकीलों को नामांकित किया गया है।

6. संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में कानूनी साक्षरता:

जम्मू और कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण (जेकेएलएसए) ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में 50 कानूनी सहायता क्लिनिक (एलएसी) स्थापित किए हैं। माह के दौरान, इन क्लीनिकों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों से 1583 लोग लाभान्वित हुए।

7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए):

नालसा ने 8 अगस्त 2021 को अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट और कानूनी सेवा मोबाइल एप्लिकेशन जारी किया। यह मोबाइल ऐप मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने वाले नागरिकों की पहुंच बढ़ाएगा। यह मोबाइल एप्लिकेशन नागरिकों को स्मार्टफोन से 24x7 कानूनी सहायता आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। नागरिक अपने कानूनी सहायता आवेदन/कानूनी सहायता प्राप्त मामलों पर भी नज़र रख सकेंगे। यह मोबाइल ऐप पीड़ित मुआवजा योजना के लिए एक ऑनलाइन मंच भी प्रदान करेगा और अपराध के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए तत्काल/अंतरिम मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल करने और अदालत से प्राप्त निर्देशों को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें पीड़ित मुआवजा आवेदन/निर्देश की प्रगति पर नज़र रखने का भी प्रावधान है। एनएएलएसए द्वारा ई-लोक अदालतों के आयोजन के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता सहित मध्यस्थता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन वाणिज्यिक मामलों में प्रि-लिटिगेशन चरण में मध्यस्थता याचिका दायर करने की सुविधा प्रदान करेगा। अनुपालन बोझ में कमी के इन तीन उपायों को न्याय विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2021 तक पूरा किया जाना था जो अब पूरे हो गए हैं।

*****